

मुख्य समाचार

1. सरकारी भूमि पर वर्षों से बसे गरीब व भूमिहीन लोगों के मकानों को रियायत देने के लिए नीति बनाने पर विचार करेगी सरकार।
2. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा—प्रदेश में एम्स व पीजीआई स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
3. राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा—औषधीय पौधों के वैज्ञानिक उपयोग से हिमाचल में हरित उद्यम राजधानी बनने की क्षमता।
4. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एम.आई.एस के तहत सी ग्रेड सेब खरीद की नई व्यवस्था को बागवानों के साथ अन्याय बताया।
5. ऊना जिला ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर—पूरा कर प्रदेशभर में तीसरा स्थान किया हासिल।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्षों से सरकारी भूमि पर बसे गरीब व भूमिहीन लोगों के मकानों को रियायत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार एक नीति बनाने पर विचार करेगी। हमीरपुर में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अतिक्रमण के मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का अध्ययन कर रही है और इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।.....

मुख्यमंत्री सुखविन्द सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान जहां गरीब व भूमिहीन लोगों को अतिक्रमण के मामलों में रियायत देने के लिए नीति बनाने की घोषणा की वहीं स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में 6 सौ 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज अगस्त महीने में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित करवाने और सुपर स्पैसलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि लोगों को प्रदेश में ही एम्स व पीजीआई स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर योजना में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर में हुए भ्रष्टाचार के जांच की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हमीरपुर में करीब एक सौ 30 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के सबसे बड़े बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है और वर्तमान बस अड्डे की जगह लगभग दो सौ करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सीटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में करीब 19 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नगर निगम कार्यालय के भवन का शिलान्यास और छोटे व्यापारियों व महिला स्वयं सहायता समूह के लिए निर्मित दुकानों व ग्रामीण हाट का उदघाटन भी किया।

राज्यपाल

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा है कि औषधीय पौधों के वैज्ञानिक उपयोग से हिमाचल प्रदेश में बागवानी केन्द्र के साथ—साथ हरित उद्यमिता की राजधानी बनने की क्षमता है। राज्यपाल आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औषधीय जड़ी—बूटियों, सुगन्धित पौधों और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों

का समृद्ध भंडार है। कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि वैज्ञानिक खेती, मूल्य संवर्धन और नवाचार के माध्यम से इस भंडार का उपयोग कर हजारों युवाओं के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एम.आई.एस के तहत सी ग्रेड सेब खरीद की नई व्यवस्था के राज्य सरकार के फैसले को बागवानों के साथ सरासर अन्याय बताया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार सेब खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के बड़े-बड़े दावे कर रही है वहीं ज़मीनी हकीकत में बागवानों के अधिकारों पर कैंची चलाई जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नए नियमों के अनुसार अब एक बागवान से अधिकतम केवल 30 बोरी सी ग्रेड सेब ही खरीदा जाएगा जो सीधे तौर पर बागवानों के हितों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बागवानों को राहत देने के बजाए हर रोज नई गाईडलाईन जारी कर उनका मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा बागवानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रदेश सरकार के इस जनविरोधी फैसले के खिलाफ बागवानों की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक पूरी मजबूती के साथ बुलंद करती रहेगी।

जनगणना

ऊना जिला ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण व मकानों की गणना का कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा कर प्रदेशभर में तीसरा स्थान हासिल किया है। उपायुक्त जतिन लाल ने इस उपलब्धि पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 चार्ज अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि जनगणना राष्ट्र निर्माण की आधारभूत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विकास योजनाओं के निर्माण व प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध होते हैं।

बिक्रम ठाकुर

भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल करार दिया है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, कुशासन और प्रशासनिक विफलताओं को नया रिकार्ड बनाकर इतिहास में दर्ज होगी। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार बेहतर शासन के दावे करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है।

उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय स्वीकृत नालागढ़ मैडिकल डिवाइस पार्क के लिए केन्द्र सरकार ने एक सौ करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी कर दी थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने ये राशि वापिस कर प्रदेश के हजारों युवाओं के रोजगार के अवसर छीन लिए। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खनन माफिया सक्रिय है और सरकार से जुड़े लोग खनन से लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री के मिशन रिपीट के दावे पर पलटवार करते हुए बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम से कांग्रेस की वास्तविक स्थिति सबके सामने आ चुकी है और प्रदेश की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है।

प्राकृतिक खेती

केन्द्र सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। सोलन जिला में करीब 2 हजार 5 सौ हैक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। आत्मा परियोजना के निदेशक हीरा लाल आजाद ने बताया कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कलस्टर बनाकर किसानों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य रासायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने और किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है।

मुख्य समाचार एक बार फिर''

1. सरकारी भूमि पर वर्षों से बसे गरीब व भूमिहीन लोगों के मकानों को रियायत देने के लिए नीति बनाने पर विचार करेगी सरकार।
2. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा—प्रदेश में एम्स व पीजीआई स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
3. राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा—औषधीय पौधों के वैज्ञानिक उपयोग से हिमाचल में हरित उद्यम राजधानी बनने की क्षमता।
4. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एम.आई.एस के तहत सी ग्रेड सेब खरीद की नई व्यवस्था को बागवानों के साथ अन्याय बताया।
5. ऊना जिला ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर—पूरा कर प्रदेशभर में तीसरा स्थान किया हासिल।